केंद्रीय बजट 2024-25
एक नज़र में

नीतिगत अनिश्चितताओं से वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने के बावजूद भारत का आर्थिक विकास एक उत्कृष्ट उदाहरण बना हुआ है तथा आने वाले वर्षों में भारत इसी प्रकार प्रगति की राह पर अग्रसर रहेगा। 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बजट में रोज़गार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी के लिए पर्याप्त अवसरों के सृजन हेतु 9 प्राथमिकताओं के संबंध में स्थायी प्रयास की परिकल्पना की गई है। ये प्राथमिकताएं हैं कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोज़गार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार।

कृषि, एमएसएमई, विनिर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किये गये हैं। गरीब, महिलाएं, युवा और किसान सरकार के प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं। रोज़गार और कौशल के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत, रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की गई। योजना 'क' के तहत, सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को एक महीने का वेतन प्रदान किया जाएगा। योजना 'ख' विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार सृजन को बढ़ावा देगी और योजना 'ग' नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं और देश में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ से अधिक की घोषणा भी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने की।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि तरुण श्रेणी के तहत ऋण लेने वाले और सफलतापूर्वक भुगतान करने वाले उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र को पीपीपी मोड में स्थापित किया जाएगा। मंत्री ने घोषणा की कि सरकार पांच साल में एक करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना शुरू करेगी। औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास-प्रकार के आवास के साथ किराये के आवास को पीपीपी मोड में सुगम बनाया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा, सरकार घरेलू उत्पादन और महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापित करेगी। उन्होंने कहा, 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14

बड़े शहरों के लिए पारगमन-उन्मुख विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की घोषणा की, जिसके तहत 10 लाख करोड़ रुपये से एक करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का चौथा चरण शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नाबालिगों की आर्थिक सुरक्षा के लिए एनपीएस (वात्सल्य) योजना शुरू की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कैंसर रोगियों को राहत देने के लिए तीन और दवाओं को सीमा शुल्क से छूट देने की भी घोषणा की। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत करने की भी घोषणा की गई। उन्होंने कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट की सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का भी प्रस्ताव रखा। भारतीय स्टार्टअप प्रणाली को मजबूत करने के लिए उन्होंने सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा।

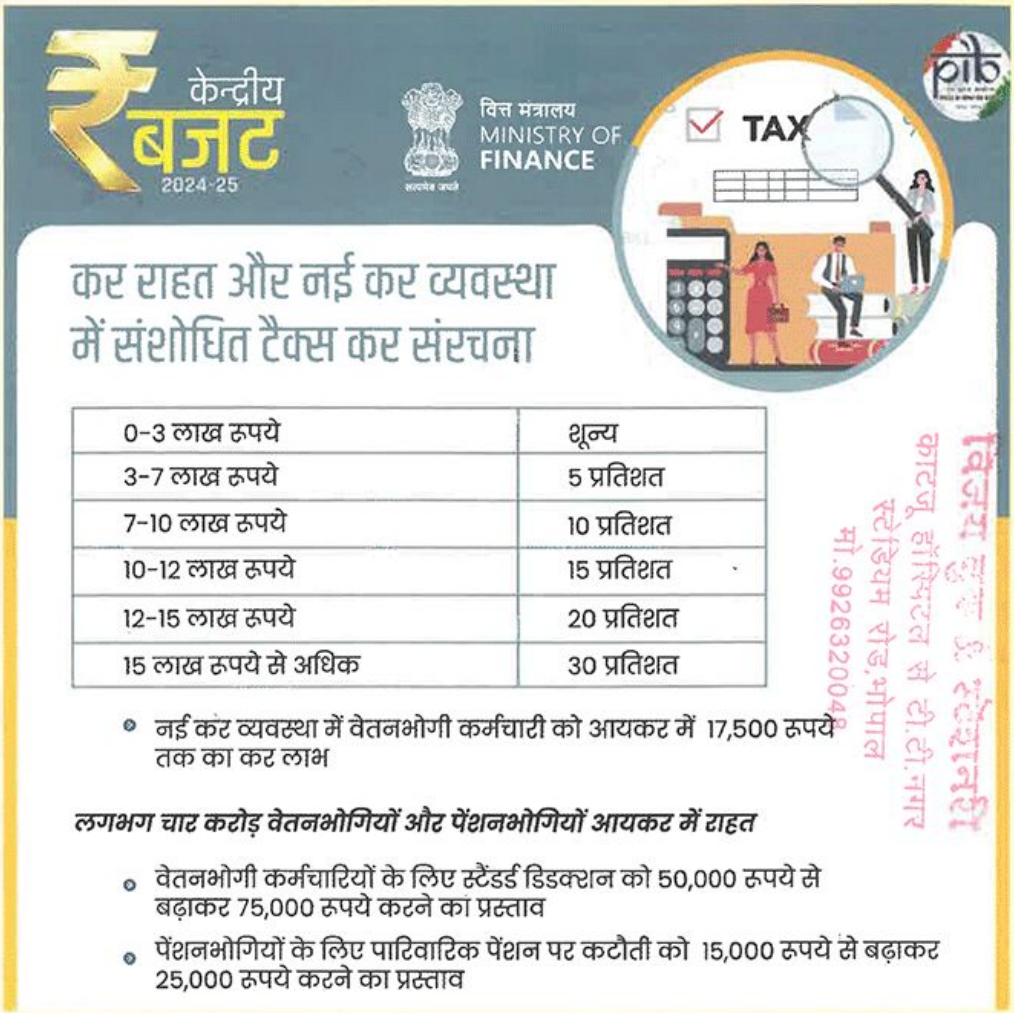

वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत आयकर के संबंध में दो बड़ी घोषणाएं कीं। नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी जाएगी और नई कर व्यवस्था स्लैब दरों में संशोधन किया गया है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य व्यक्तियों को कर राहत प्रदान करना और कर संरचना को सरल बनाना है। ❑

केन्द्रीय बजट 2024-25

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

कर राहत और नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स कर संरचना

0-3 लाख रुपये	शून्य
3-7 लाख रुपये	5 प्रतिशत
7-10 लाख रुपये	10 प्रतिशत
10-12 लाख रुपये	15 प्रतिशत
12-15 लाख रुपये	20 प्रतिशत
15 लाख रुपये से अधिक	30 प्रतिशत

- नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपये तक का कर लाभ

लगभग चार करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों आयकर में राहत

- वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव
- पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव

काटजू हॉस्पिटल से टी.टी.नगर
स्टेडियम रोड,भोपाल
मो.9926320048

अगली पीढ़ी के सुधार

- प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था के डिजीटलीकरण की रफ्तार को बढ़ाएगी
- जन विश्वास विधेयक 2.0 कारोबार करने में आसानी को और बेहतर बनाएगा
- राज्यों को कारोबार सुधार कार्य योजना के कार्यान्वियन और डिजिटलीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
- डेटा प्रबंधन और शासन को बेहतर बनाने के लिए सेक्टर-वार डेटाबेस
- एक समिति नई पेंशन योजना की समीक्षा करेगी, ताकि वित्तीय विवेकशीलता को बनाए रखने के साथ प्रासंगिक मुद्दों का समाधान किया जा सके

विभिन्न क्षेत्रों पर बजट घोषणाओं के प्रभाव के व्यापक विश्लेषण और नौ प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के गहन अध्ययन के साथ, केंद्रीय बजट 2024-25 पर योजना का सितंबर अंक अवश्य पढ़ें!